दुकानदार पर लाठी-डंडों से हमला

जयपुर। राजधानी के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में उधार सब्जी देने से मना करना एक फल-सब्जी विक्रेता को भारी पड़ गया। करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले दुकान के अंदर मारपीट की, फिर उसे घसीटकर सड़क पर लाकर बेरहमी से पीटा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी कई बार उधार सब्जी लेकर गया था और पैसे नहीं लौटाए। इस बार उधार देने से मना करने पर विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित पप्पू लाल सैनी ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान है। 27 अप्रैल की रात कुंडा रोड निवासी मोहित शर्मा नींबू खरीदने आया था। नींबू लेने के बाद जब पैसे मांगे गए तो उसने भुगतान से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया। जिन्होंने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जहां आरोपियों ने पहले दुकान के अंदर मारपीट की और सीसीटीवी का पता चलने पर उसे बाहर सड़क पर ले जाकर फिर से पीटा। हमले में उसके हाथों और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों ने बीच-बचाव कर उसे छुड़वाया।

जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 13037 करोड़ रु. की केन्द्रीय मंजूरी मिली

केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के 20 दिन बाद ही जारी हुआ स्वीकृति आदेश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना के लिए 13037.66 करोड़ रुपये की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है।

- **फेज-2 में 41 किलोमीटर के कॉरिडोर पर 36 स्टेशन बनाए जाएंगे**
- **परियोजना में केंद्र व राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी**

मंजूरी के करीब 20 दिन बाद जारी इस आदेश से शहरवासियों को बड़ी सौगात मिली है।

परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही यह परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को नया आयाम देगी।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रथम चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए शीघ्र कार्यादेश जारी करने की तैयारी की जा रही है। शेष पैकेज के लिए निविदा प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है।

मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत इक्विटी मिलने से राज्य पर वित्तीय भार कम होगा। परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पूर्ण होने पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और सुगम होने की उम्मीद है।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम

वर्ष 2026-27 में करीब 1500 करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य तय

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास समग्र रूप से किया जा रहा है, जिसमें विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, सड़कों के निर्माण एवं सुधार, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का आधुनिक एवं सुदृढ़ विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रीको प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन एवं रखरखाव पर लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाया जा सके।

औद्योगिक इकाइयों को आगजनी जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखने एवं बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से रीको द्वारा 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तथा 37 अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र भिवाड़ी (चौपानकी, खुशखेड़ा), बीकानेर (करणी औद्योगिक क्षेत्र चरण प्रथम एवं द्वितीय), बोरानाडा, चुरू, जयपुर (जैतपुरा), जोधपुर (बासनी), नागौर (आईआईडी सेंटर एवं एसजीसी परबतसर), सवाई माधोपुर (खेरदा, टोंक, हिंडौन सिटी) तथा श्रीगंगानगर में औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ (चरण द्वितीय) सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त आबूरोड, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बोरानाडा, चुरू, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, नीमराना, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में 37 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। रीको द्वारा विद्युत आपूर्ति को निर्बाध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य भी करवाये जायेंगे।

रीको के इन प्रयासों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

भीषण गर्मी और हीटवेव से आमजन रहें सुरक्षित : मुख्यमंत्री

बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिला एवं बीमार व्यक्ति बरतें विशेष सावधानियां

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के दौर के मद्देनजर आमजन से एहतियात बरतने की अपील करते हुए राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना करने की सलाह दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें। विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति अतिरिक्त ध्यान रखें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर अनावश्यक निकलने से बचें।

उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक के गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी, तेज बुखार की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं

- **संवेदनशीलता के साथ पशु-पक्षियों की करें देखभाल : भजनलाल शर्मा**

अथवा टोल-फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर संपर्क करें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यस्थलों पर नियोजित श्रमिकों, किसानों एवं पशुपालकों से लू एवं हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने आमजन से संवेदनशीलता के साथ पशु और पक्षियों के खाने और पानी की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर समेत 7 शहरों में अंधड़ और बारिश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर सहित करीब सात शहरों में बारिश हुई, जबकि कोटा, अलवर और दौसा में ओलावृष्टि दर्ज की गई। अंधड़ के दौरान चूरू जिले के बीदासर में बिजली का तार टूटकर एक मकान की छत पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई।

बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई, हालांकि एक दर्जन से अधिक शहरों में पारा अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

इसी बीच धौलपुर में गर्मी के चलते एक ट्रेन के कोच के निचले हिस्से में आग लगने की घटना सामने आई। आग ब्रेक पैडल के पास लगी थी, जिसे समय रहते बुझा लिया गया। प्रारंभिक रूप से आग का कारण अत्यधिक गर्मी माना जा रहा है।

सार-समाचार

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह से मिले प्रतिनिधि

जयपुर (कासं)। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा के नेतृत्व में, गजराज सिंह; महेंद्र सिंह; राजेंद्र सिंह जोधा; तथा तरुण कुमार बंसल, अध्यक्ष एचआरएआर एवं सचिव एफएचटीआर सहित फैडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने, जोधपुर-मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख ट्रैवल एवं होटल एसोसिएशनों झारा और ताज के सदस्यों के साथ, बुधवार को कर्तव्य भवन में केंद्रीय पर्यटन-संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार से मुलाकात की। बैठक में पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिनमें होटल वर्गीकरण मानदंड, व्यवसाय करने में सुगमता, विदेशी पर्यटकों के लिए वैट रिफंड व्यवस्था, वीज़ा नियम, भूमि रूपांतरण से संबंधित चुनौतियां तथा उद्योग को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दे शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय मंत्री को आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर एवं मारवाड़ ट्रैवल मार्ट, जोधपुर, जो सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले हैं, के लिए औपचारिक आमंत्रण भी दिया। इन आयोजनों का उद्देश्य राजस्थान के पर्यटन को नई दिशा देना है, विशेष रूप से अनुभवात्मक पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत तथा हस्तशिल्प आधारित पर्यटन की अपार संभावनाओं को प्रोत्साहित करना, खासकर थार मरुस्थल क्षेत्र में।

मुहाना मंडी में पेयजल व्यवस्था की मांग

जयपुर (कासं)। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेश तंवर ने महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी की पेयजल समस्या को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सैनी को ज्ञापन सौंपा। योगेश तंवर ने सैनी से आग्रह किया कि मुहाना मंडी परिसर में नई 4 इंच की पेयजल वितरण लाइन डलवाने के कार्य में मदद करें। सैनी ने समस्या के समाधान के लिए तत्काल जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के लिए दूरभाष से निर्देश दिए। तंवर ने बताया कि मुहाना मंडी में वर्ष 2008 से आज तक पेयजल वितरण व्यवस्था डगमगाई हुई है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आज भी पेयजल सप्लाई ना के बराबर है। व्यापारी अपने खर्चे पर टैंकरों से दुकानों में पानी डलवाते हैं, पीने के पानी के लिए अपनी अपनी दुकानों पर पानी के ठंडे कैंपर रखवाकर बरसों से काम चला रहे हैं। जबकि रोजाना मंडी परिसर में 10 से 15 हजार के व्यापारी, किसान, मजदूर, ग्राहक एवं वाहन चालक आते हैं। मंडी में विद्यमान पेयजल सप्लाई लाइन वर्ष 2018 में डाली गई थी, लेकिन वह भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहां लोगों को पेयजल के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मंडी परिसर में पेयजल वितरण का एक भी स्थायी ढांचा भी नहीं है। पानी की एक टंकी बनाई हुई है, लेकिन उससे भी वितरण नहीं हो पाता है। तंवर ने बताया कि मुहाना मंडी परिसर में लगभग 1500 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। लंबे समय से संगठन समय समय पर पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन देता आ रहा है, लेकिन अभी तक भी समाधान नहीं हो पाया है।

मेघा सोनी को मिला राष्ट्रीय रत्न सम्मान

जयपुर। पिंकसिटी की मेघा सोनी को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उभरते लक्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान मेघा सोनी को उनके ब्रांड गजाह के लिए दिया गया, जिसने कम समय में सिल्वर ज्वैलरी क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आधुनिक डिजाइनों, पारंपरिक कला और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण ब्रांड को ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रियता मिली है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं पद्मश्री सम्मानित कंगना रनौत ने मेघा सोनी को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया।

तीन अफसरों को मिली डीजीपी डिस्क

जयपुर। पुलिस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित रेंज समीक्षा बैठक के बीच एक विशेष सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में लंच के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया और सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी को विदाई दी गई। समारोह के मुख्य चरण में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने विभाग के तीन अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं और विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले अधिकारियों में भरतपुर रेंज आईजी कैलाश विश्नोई, कोटा रेंज आईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल और भीलवाड़ा के दुर्गालाल ढोली शामिल रहे। इसी कड़ी में कोटा रेंज आईजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे राजेन्द्र प्रसाद गोयल का अभिनंदन किया गया। डीजीपी शर्मा, डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल और डीजी स्पेशल ऑपरेशन्स आनंद श्रीवास्तव ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके पुलिस विभाग में लंबे और गौरवशाली कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके भविष्य के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं। समारोह के दौरान पीएचक्यू के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी रेंज आईजी और जयपुर व जोधपुर के पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे।

पंचायत-निकाय चुनाव की तिथि बढाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 18 मई को

हाईकोर्ट पहले तारीख बढ़ाने पर सुनवाई करेगी, अवमानना याचिका बाद में तय होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तिथि बढ़ाने के संबंध में दायर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को पहले तय किया जाएगा और उसके बाद मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक संयम लोढा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 18 मई को रखी है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत ने 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है। यह अदालती आदेश की सीधे तौर पर अवमानना है। वहीं पूर्व में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि हाईकोर्ट ने गत 14 नवंबर को आदेश जारी कर पंचायतों और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने के आदेश दिए थे। स्थानीय निकाय के लिए करीब 1.26 लाख और पंचायत चुनाव के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसमें से 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल सत्र शुरू हो चुका है और मई-जून में भीषण गर्मी पडेगी। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून व कृषि कार्य में आमजन व्यक्ति रहेगा। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर में पूरा होगा। वहीं राज्य चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन माह का समय लगेगा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी तीस सितंबर तक आने की संभावना है। इसलिए चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

सीपी जोशी पुन: बने संसद की याचिका समिति के सभापति

चित्तौडगढ़ (कासं)। चित्तौडगढ़ सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका (पिटीशन) समिति का पुन: सभापति मनोनीत किया है।

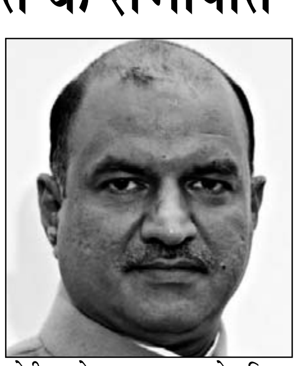

सांसद जोशी को संसद की 15 सदस्यीय लोकसभा की याचिका समिति का सभापति व अन्य 14 सांसदों को सदस्य बनाया गया है। जिनमें सदस्य सांसद एंटो एंटनी, सुखदेव भगत, राजू बिष्टा, गुरमीत सिंह, बस्तीपति नागराजू, मीतेश पटेल बाकाभाई, डॉ. राजकुमार सांगवान, कमलजीत शेहरावत, देवेश शाक्य, मंजू शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा, अभय कुमार सिन्हा व राजमोहन उन्निथन, मनोज तिवारी है। सांसद जोशी वर्तमान में संसद की याचिका समिति के सभापति के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम समिति व ऊर्जा समिति में सदस्य हैं। पूर्व में बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 बिल की संयुक्त समिति के सभापति भी रह चुके हैं।सांसद जोशी ने याचिका समिति के पुन: सभापति मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। गौरतलब हैं की लोकसभा की याचिका समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके कार्य आम जनता की ओर से संसद में उठाई गई याचिकाओं पर विचार करना, याचिकाओं पर सरकार से राय मांगना, याचिकाओं पर रिपोर्ट देना, याचिकाओं के निपटान के लिए निर्देश देना, याचिकाओं से जुडे मामलों में मंत्रालय के विचारों पर विचार करना, याचिकाओं के निपटान के लिए सभा में रिपोर्ट पेश करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आदि है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीव गणना की तैयारियां पूरी

जयपुर (कासं)। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में आगामी वार्षिक वन्यजीव गणना को लेकर वन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष की गणना कई मायनों में विशेष रहने वाली है, क्योंकि पहली बार महिला कार्मिकों के तीन दल इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे।इसके चलते बुधवार को सहायक वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़, रेंजर शुभम शर्मा और फॉरेस्टर राजाराम मीणा ने नाहरगढ़ रेंज का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन्यजीवों के लिए बनाए गए 10 नए वाटर पॉइंट्स और निगरानी के लिए तैयार किए गए मचानों का बारीकी से जायजा लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए वन्यजीवों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता बनी हुई है।

वन विभाग के अनुसार वन्यजीव गणना 1 मई 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई 2026 को शाम 5 बजे तक 24 घंटे के 'वाटर होल सर्वे' के रूप में संचालित की जाएगी।

राजस्थान में डेयरी क्षेत्र बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र ग्रामीण विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 प्रतिशत है। यह हिस्सा फसलों के योगदान (42.61 प्रतिशत) से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि बदलते कृषि परिदृश्य में डेयरी क्षेत्र किसानों के लिए नियमित आय का मजबूत स्त्रोत बन चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में डेयरी विकास को नई गति मिली है। पिछले दो वर्षों में दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे राजस्थान श्वेत क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। राज्य में दुग्ध संकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जबकि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। आगामी दो वर्षों में इसे 74 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरस डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क के विस्तार से दुग्ध उत्पादों के विपणन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नए सरस बूथों की स्थापना के साथ राजस्थान से अन्य राज्यों में प्रतिदिन एक लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय सेना को भी सरस द्वारा प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।दूध उत्पादकों को क्रय मूल्य वृद्धि के रूप में वर्ष 2025-26 में लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा हुआ है।

सरस स्वरोजगार योजना के तहत 2,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक विस्तार की दिशा में भी कार्य जारी है।

पिछले दो वर्षों में 3,525 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिससे सहकारी तंत्र को मजबूती मिली है। वर्ष 2025-26 में आरसीडीएफ एवं संबद्ध दुग्ध संघों का कुल टर्नओवर 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने दूध उत्पादकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 1,386 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।

अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग पर 35 सिलेंडर जब्त

जयपुर। राजधानी में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संयुक्त टीम ने सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 35 अवैध गैस सिलेंडर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा विशेष प्रवर्तन दल का गठन किया गया।

पुलिस थाना सांगानेर सदर से मिली सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ने गोविंदपुरा (बक्षावाला), शिकारपुरा रोड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 35 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर जब्त की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार इस तरह के अवैध रिफिलिंग केंद्र शहर में होने वाली आगजनी और विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकते हैं।

ईंट-भट्टों से 150 दिनों तक रॉयल्टी वसूली को हाईकोर्ट में चुनौती

ईएनटी भट्टा संघ भरतपुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 122 दिन ही प्रदेश में ईंट-भट्टे कार्यरत रहते हैं, तो फिर ज्यादा दिनों का टैक्स क्यों वसूला जा रहा है?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में ईएनटी भट्टा संघ भरतपुर ने 150 दिनों तक वसूली जाने वाली रॉयल्टी टैक्स को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईंट-भट्टे 1 मार्च से 30 जून तक ही प्रतिवर्ष (122 दिन) ही कार्य कर सकते हैं। परंतु राज्य सरकार द्वारा जिस फार्मूले से रॉयल्टी टैक्स की गणना की जा रही है, उसमें 150 अंक को आधार बनाया हुआ है।

- **याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियांशा गुप्ता ने अदालत में सी.ए.जी. की 2 रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें रॉयल्टी गणना के फॉर्मूले में 150 अंक को 150 दिन बताया गया है।**
- **पूरे प्रकरण को सुनने के बाद न्यायाधीश अनरूप सिंघी ने कहा कि, 14 जुलाई को अगली सुनवाई पर महाधिवक्ता, अदालत को यह फार्मूला समझने में मदद करे और स्पष्ट करें कि यह 150 अंक कहां से आए।**

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनरूप सिंघी की एकलपीठ ने कहा कि, एडिशनल गर्वमेंट काउंसिल द्वारा विभाग की ओर से दिए गए शपथ पत्रों में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि, यह 150 का अंक क्या है? कहीं यह 150 अंक पुराने फार्मूले के हिसाब से 150 दिन तो नहीं है? अदालत ने 14 जुलाई को अगली तारीख देते हुए कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता, अदालत को यह फार्मूला समझने में मदद करे और स्पष्ट करें कि यह 150 अंक कहां से आए। इस मामले के तथ्यों के अनुसार 19 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि, प्रदेश में केवल 122 दिन ही ईंट-भट्टों का संचालन हो सकेगा। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिए थे, क्योंकि दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण होता है, इसमें ईंट भट्टों के संचालन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत ने गर्मियों के मौसम में ही ईंट-भट्टों के संचालन के आदेश दिए थे।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियांशा गुप्ता ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुराने "राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स-2017" के मुताबिक 150 दिनों का फॉर्मूला लगाकर रॉयल्टी वसूली जा रही है, जो कि खुली मनमानी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में सी.ए.जी. की 2 रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें रॉयल्टी गणना के फॉर्मूले में 150 अंक को 150 दिन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह स्पष्ट करने की कोशिश की, ईंट भट्टा निर्माताओं द्वारा कितनी टन ईंटे बनाई जाती है, उसकी रॉयल्टी आंकने में यह 150 का अंक इसलिए जोड़ा जोता था, क्योंकि पूर्व में इतने ही दिन (9 माह) ईंट-भट्टे कार्यरत रहते थे। दूसरी ओर खनन विभाग की ओर से कई बार शपथ पत्र पेश किए गए, जिनमें 150 अंक को अलग-अलग नामों और तर्कों से व्याख्या करने की कोशिश की गई, परंतु अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए।

आयुष्मान आईपीडी टावर को लेकर तेज़ हुई तैयारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आयुष्मान आईपीडी टावर के निर्माण और संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जेडीए अधिकारियों के बीच लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। जिससे दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय भी मजबूत हुआ है।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए स्पष्ट डेडलाइन तय की गई है। योजना के अनुसार दिसंबर-जनवरी में कुछ विभागों को शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में टावर की 3 से 4 मंजिलों को चालू करने की तैयारी है, जिससे मरीजों को जल्द राहत मिल सके। करीब 1200 बेड क्षमता वाले इस आईपीडी टावर में पहले चरण में लगभग 200 बेड तैयार किए जाएंगे। साथ ही ओपीडी सेवाएं और आवश्यक जांच केंद्र शुरू करने की भी योजना है। टावर का इंटीरियर कार्य अंतिम चरण में है और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन का मानना है कि टावर शुरू होने से अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इधर सवाई मानसिंह अस्पताल में तैयार हो चुका अत्याधुनिक कार्डियक सेंटर अभी भी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसे शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। प्रिंसिपल डॉ. माहेश्वरी ने बताया कि यह सेंटर लगभग तैयार है और जल्द आवश्यक मशीनों की इंस्टॉलेशन पूरी कर इसे चालू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकारी क्षेत्र में इस स्तर का हाईटेक कार्डियक सेंटर देश में पहला होगा। इस सेंटर में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी समेत हृदय रोगों की सभी जांच और इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। साथ ही 2डी ईको, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, आधुनिक आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।